



Reading Material on :- **Further Investigation**

Workshop Dated 2/2/2026

District Court Durg (C.G.)

Prepared By-

Smt. Pallavi Gupta

ADPO, Durg (C.G.)

FURTHER INVESTIGATION

WORKSHOP DATED 02.02.2026

DISTRICT COURT DURG

आपराधिक न्याय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है सत्य की खोज और जब कभी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक विवेचना में कोई तथ्य छूट गया है, कोई साक्ष्य सामने नहीं आ पाया है या कोई नई जानकारी प्राप्त हुई है वही से Further Investigation की आवश्यकता जन्म लेती है।

Further Investigation क्या है?

Further Investigation का अर्थ है —

चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद, पहले की जाँच को पूरा करने हेतु आगे की जाँच।

यह न तो Fresh Investigation है और न ही Re- Investigation बल्कि पहले की जाँच का पूरक (Suppliment) भाग है।

Criminal Procedure Code की धारा 173 (B) व Bharti Nyay Surksha Sahita के धारा 193 (9) में Further Investigation के संबंध में प्रावधान दिया हुआ है।

यह जाँच —

- नई गवाही मिलने पर
 - नया दस्तावेज सामने आने पर
 - नया आरोपी उजागर होने पर
- या किसी तथ्य के छूट जाने पर की जाती है।
यह पहली जाँच को रद्द नहीं करती, बल्कि उसे पूरक (Suppliment) बनाती है।

धारा 173 (8) Criminal Procedure Code में Bharti Nagrik Suraksha Sahita की धारा 193 (9) के अंतर्गत 90 day का Golden Rule शामिल किया गया है।

धारा 193 (9) के अनुसार :—

पुलिस न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने के बाद 90 दिन के भीतर

- आगे की जाँच Further Investigation कर सकती है।
- आगे पूरक चार्जशीट (Supplementary Charge - Sheet) दाखिल कर सकती है।

90 दिन के बाद —

- पुलिस स्वतः (अपने आप) Further Investigation कर सकती है।
- कोर्ट की अनुमति (leave of Court) अनिवार्य हो जाती है।

विनय त्यागी विरुद्ध इरशाद अली 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है Further Investigation किसी के कहने पर भी हो सकता है यदि उसका उद्देश्य सत्य तक पहुँचना है।

- अतः धारा 193 (9) Bhartiya Nagrik Suraksha Sahita के तहत चार्जशीट के बाद 90 दिनों तक पुलिस स्वतंत्र रूप से Further Investigation कर सकती है किंतु 90 दिनों के पश्चात् न्यायालय की अनुमति अनिवार्य है।
- Bhartiya Nagrik Suraksha Sahita में Further Investigation में जो 90 दिन का प्रावधान किया गया है वह अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों के लिए ही प्रभावी है।
- पुलिस 90 दिन के भीतर पूरी सतर्कता से जाँच करेगा तथा देरी होने पर अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में आवेदन दिया जा सकता है वहीं यदि पुलिस द्वारा 90 दिन के बाद बिना न्यायालय की अनुमति के पूरक चालान पेश करता है तो बचाव पक्ष द्वारा ई-लीगल Further Investigation कहते हुए क्वेश तथा डिस्चार्ज के लिए आवेदन दे सकता है।

Bhartiya Nagrik Suraksha Sahita बनाम Criminal Procedure Code की तुलना

Cr.P.C.	B.N.S.S.
1. अनुमति की समय सीमा स्पष्ट नहीं। 2. जजमेंट से विकसित – 1. स्टेट ऑफ तेलंगना Vs हबीब अब्दुल्ला जीलानी 2023 SCC ऑन लाईन सु. को. में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चार्ज शीट दाखिल होने के बाद भी यदि न्याय के हित में हो तो Further Investigation पूर्णतः वैध है। 2. सी.बी. आई Vs थोमांडुरु हन्ना विजय लक्ष्मी में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य छूट गया है तो Further Investigation न केवल अधिकार है बल्कि आर्टिकल 21 संविधान के तहत संवैधानिक दायित्व भी है। 3. Cr.P.C. के तहत Transparency कम थी।	1. 90 दिन की स्पष्ट समय सीमा। 2. कानून में स्पष्ट लिखा है। 3. B.N.S.S. में Transparency ज्यादा है।

अतः स्पष्ट है कि B.N.S.S. में यह प्रावधान **Investigation** में डिस्सीप्लिन और आरोपी को प्रोटेक्शन लाने के लिए जोड़ा गया है।

Further Investigation क्यों आवश्यक है —

- विवेचना कोई गणतीय प्रक्रिया नहीं है।
- यह मानव बुद्धि, परिस्थिति और उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित होती है।
- यह संभव है कि प्रारंभिक जाँच में कोई गवाह छूट गया हो।
- कोई दस्तावेज बाद में मिला हो।
- कोई वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हुआ हो।

ऐसी स्थिति में यदि आगे की जाँच की अनुमति न दी जाये तो सत्य अधूरा रह जायेगा और न्याय प्रभावित होगा। हसन भाई कुरैशी विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात 2004 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि नई सामग्री सामने आती है तो जाँच को आगे न बढ़ाना न्याय के साथ अन्याय होगा।

Further Investigation और Re- Investigation में अंतर —

Further Investigation का मतलब है — पहले से की गई वैध जाँच को आगे बढ़ाना, उसमें नया साक्ष्य जोड़ना न कि पहले की जाँच को मिटाना।

Re- Investigation (पुनः जाँच) क्या है?

Re- Investigation का मतलब है — पहले की पूरी जाँच को रद्द करके, नई सिरे से जाँच कराना।

यह साधारण अधिकार नहीं बल्कि असाधारण स्थिति में ही होता है।

- इसके संबंध में Cr.P.C./ B.N.S.S. में सीधा प्रावधान नहीं है।
- यह केवल संवैधानिक न्यायालयों द्वारा आदेशित हो सकता है यदि यह पाया जाता है कि जाँच पक्षपातपूर्ण, जानबूझकर आरोपी को बचाया हो, फर्जी जाँच हो या निष्पक्ष जाँच असंगत हो तब दिया जा सकता है केवल उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा —
पूजा पाल विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया (2016) में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया है कि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जाँच के लिए दुबारा जाँच जरूरी है।

कब Re- Investigation होती है?

- जॉच पक्षपातपूर्ण हो।
- पुलिस ने जानबूझकर आरोपी को बचाया हो।
- फर्जी जॉच।
- जनता का न्याय प्रणाली से विश्वास डगमगा जाए।

Pooja Pal Vs Union Of India (2016) 3 Scc 135 में माननीय **Supreme Court** ने यह अभिनिर्धारित किया है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जॉच के लिए दुबारा जॉच जरूरी है।

अतः 193 (9) B.N.S.S. में –

- अभियोजन को सत्य खोज की शक्ति दी।
- आरोपी को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाया।
और न्यायालय को नियंत्रण की भूमिका दी है।

अतः सत्य सामने आने से कानून को रोकना न्याय को रोकना है।

(श्रीमती पल्लवी गुप्ता)
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
जिला अभियोजन निदेशालय
जिला दुर्ग, (छ0ग0)।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):

यह रिसर्च पेपर लेखक के व्यक्तिगत अध्ययन एवं विश्लेषण पर आधारित है तथा इसमें व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं। यद्यपि इसे सटीक एवं अद्यतन रखने का प्रयास किया गया है, तथापि इसमें त्रुटि या सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे पूर्णतः प्रामाणिक अथवा विधिक सलाह के रूप में न माना जाए। किसी भी विधिक निर्णय से पूर्व संबंधित कानूनों एवं विशेषज्ञ परामर्श का संदर्भ लिया जाना अपेक्षित है।